राजनीति के मर्दों ने वैश्याओं को भी मात दे दी है-हरिशंकर परसाई

तेवर वही, अंदाज नया .....!
साप्ताहिक

उज्जैन टाइम्स

डाक रजिस्ट्रेशन नं. मालवा डिवीजन-
L2/65/RNP/397/2024-2026

प्रधान सम्पादक : मनमोहन शर्मा

RNI No. 7583/61

● वर्ष : 63, अंक : 25 ● उज्जैन, मंगलवार दिनांक 19-03-2024 से 25-03-2024 तक ● पृष्ठ : 08 ● मूल्य : 2 रुपये

भारत में जल संकट-कितना है और हम क्या कर सकते हैं?

हाल ही में बेंगलुरु जल संकट ने भारत में बढ़ते जल संकट को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। पानी की कमी से जूझ रहे बेंगलुरु को डे जीरो (जब सरकार घरों और व्यवसायों के लिए पानी के कनेक्शन बंद कर देगी) के खतरे का सामना करना पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के आधार पर बीबीसी की एक रिपोर्ट में उन 11 वैश्विक शहरों में ब्राजील के साओ पाउलो के बाद बेंगलुरु को दूसरे स्थान पर सूचीबद्ध किया गया था, जहां पीने का पानी खत्म होने की संभावना है।

जल संकट क्या है और भारत में क्या स्थिति है?

जल संकट-जल संकट उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां किसी क्षेत्र में उपलब्ध पीने योग्य, सुरक्षित पानी उसकी मांग से कम है। विश्व बैंक जल की कमी को उस स्थिति के रूप में संदर्भित करता है जब वार्षिक प्रति व्यक्ति उपलब्धता 1000 घन मीटर से कम हो।

भारत में जल संकट के क्या कारण हैं?

पानी की बढ़ती मांग-नीति आयोग के अनुसार, भारत की पानी की मांग तेजी से बढ़ रही है। भारत की पानी की मांग 2030 तक उपलब्ध आपूर्ति से दोगुनी होगी। साथ ही, 2041-2080 के दौरान भारत में भूजल की कमी की दर वर्तमान दर से तीन गुना होगी।

कृषि के लिए भूजल का उपयोग-दोषपूर्ण फसल पैटर्न के कारण कृषि में भूजल का अधिक उपयोग होता है। पूर्व के लिए-पंजाब और हरियाणा राज्यों में जल-गहन धान की खेती। प्राकृतिक जल निकायों का अतिक्रमण-बढ़ती आबादी की बुनियादी ढांचे की जरूरतों को पूरा करने के लिए झीलों और छोटे तालाबों का विनाश हुआ है। उदाहरण के लिए-बेंगलुरु में झीलों का अतिक्रमण।

जलवायु परिवर्तन-जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून अनियमित हो गया है और कई नदियों में जल स्तर कम हो गया है। इससे भारत में जल संकट उत्पन्न हो गया है।

प्रदूषकों का निर्वहन-औद्योगिक रसायनों, सीवरों और अनुचित खनन गतिविधियों के निर्वहन से भूजल संसाधनों का प्रदूषण हुआ है।

सक्रिय प्रबंधन नीतियों का अभाव-भारत में जल प्रबंधन नीतियां समय की बदलती मांगों के साथ तालमेल बिठाने में विफल रही हैं। उदाहरण के लिए- 1882 का सुख सुविधा अधिनियम भूस्वामी को भूजल स्वामित्व अधिकार प्रदान करता है जिससे जल संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग होता है।

शासन संबंधी मुद्दे-भारत में जल प्रशासन खंडित हो गया है। जल से संबंधित विभिन्न मुद्दों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र और राज्यों के पास अपने-अपने विभाग हैं। सतही जल एवं भूजल के लिए अलग-अलग विभाग बनाये गये हैं। केंद्रीय जल आयोग (सतह जल के लिए) और केंद्रीय भूजल बोर्ड (भूजल के लिए)। राजनीतिक दलों द्वारा अंतर्राज्यीय विवादों का राजनीतिकरण करने से विवादों के त्वरित समाधान में बाधा उत्पन्न हुई है।

भारत में जल संकट के आर्थिक प्रभाव क्या हैं?

विश्व बैंक के अनुसार, पानी की कमी के कारण 2050 तक भारत की जीडीपी में 6% तक की गिरावट आ सकती है। पानी की कमी से खाद्य उत्पादन में गिरावट आएगी। इससे भारत की खाद्य सुरक्षा बाधित होगी और किसानों और खेत मजदूरों की आजीविका पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। कपड़ा, थर्मल पावर प्लांट आदि जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आई है। पानी की कमी से परेशानी हो सकती है।

घरेलू स्तर पर जल संरक्षण हेतु विचार

ओवरहेड शॉवर नहीं-घर में बाल्टी स्नान का उपयोग करें। शॉवर प्रति मिनट 913 लीटर का उपयोग करता है जबकि एक बाल्टी 20 लीटर की होती है। 5 मिनट के शॉवर बनाम बाल्टी स्नान से प्रति व्यक्ति 45 लीटर की बचत होती है, लगभग बचत180 लीटर।

शेष पेज 2 पर.....

भारत माता का परचम पूरी दुनिया में लहरा सकता है

एक धनी प्रधानमंत्री बन सकता है,
ये नेहरू ने साबित किया।
एक गरीब प्रधानमंत्री बन सकता है,
ये शास्त्री जी ने साबित किया।
एक बुजुर्ग प्रधानमंत्री बन सकता है,
ये मोरारजी ने साबित किया।
एक युवा प्रधानमंत्री बन सकता है,
ये राजीव गांधी ने साबित किया।
एक औरत प्रधानमंत्री बन सकती है,
ये इंदिरा गांधी ने साबित किया।
एक किसान प्रधानमंत्री बन सकता है,
चौ. चरण सिंह ने साबित किया।
एक राजघराने का व्यक्ति प्रधानमंत्री हो सकता है,
ये वी.पी. सिंह ने साबित किया।
एक शिक्षित एवं बहुआयामी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है,
ये पी.वी.नरसिंहा राव ने साबित किया।
एक कवि प्रधानमन्त्री बन सकता है,
ये अटल बिहारी बाजपेयी ने साबित किया।
कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है,
ये एच.डी.देवगौडा ने साबित किया।
एक प्रधानमंत्री की आवश्यकता ही नहीं है,
ये डॉ. मनमोहन सिंह ने साबित किया।
देश पर बिना प्रधानमंत्री बने भी शासन किया जा सकता है,
ये सोनिया गांधी ने साबित किया।
परन्तु एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है और इन सबसे बेहतर कार्य कर सकता है तथा भारत माता का परचम पूरी दुनिया में लहरा सकता है, ये नरेन्द्र मोदी जी ने साबित किया।
सारी कायनात लगी है एक शख्स को झुकाने में भगवान भी सोचता होगा, जाने किस मिट्टी का इस्तेमाल किया मैंने 'मोदी' को बनाने में!
जो व्यक्ति पीएम बनने से पहले यदि....
अमरीका को झुका सकता है,
भूखे नंगे देश पाकिस्तान में हडकंप मचा सकता है,
चीन जैसे गद्दार देश के अखबारों की,
सुर्खियों में आ सकता है।
तो भाई वह भारत को विश्व गुरु बना सकता है,
यह बात पक्की है!
देश की जरुरत है मोदी!

सम्पादकीय

इलेक्टोरल बॉन्ड, दूध का दूध और पानी का पानी

इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करने की कवायद स्वाभाविक ही थमने का नाम नहीं ले रही है और सर्वोच्च न्यायालय की सक्रियता लगातार रंग ला रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को एक बार फिर भारतीय स्टेट बैंक को यह कहते हुए फटकार लगाई है कि वह चयनात्मक नहीं हो सकता है, मतलब वह चुन-चुनकर सूचनाएं नहीं जारी कर सकता। उसे बॉन्ड से जुड़ी हर सूचना जनहित में जारी करनी चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड के संबंध में एक-एक सूचना का सबके सामने आना तय है और इसके लिए न्यायालय ने एसबीआई को 21 मार्च तक का समय दिया है। बॉन्ड के संबंध में सूचनाओं की जितनी बड़ी खेप सामने आ चुकी है, उससे कहीं ज्यादा बड़ी खेप का आना शेष है। बैंक जैसे ही बाकी सूचनाएं देगा, वैसे ही चुनाव आयोग उनको अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित कर देगा। दरअसल, अल्फा-न्यूमेरिक विशिष्ट नंबर का खुलासा होना भी जरूरी है, इससे साफ तौर पर पता चलेगा कि बॉन्ड किसने खरीदा और उसका लाभ किसने लिया? देश के लिए यह जानना जरूरी है कि किस पार्टी की झोली में कुल कितना चंदा गया है और किसने दिया है? सर्वोच्च न्यायालय ने एसबीआई को यहां तक कहा है कि आप अगले आदेश की प्रतीक्षा मत कीजिए, जो भी सूचनाएं हैं, सबको जारी कर दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय ने महसूस किया है कि एसबीआई चुनिंदा सूचनाएं ही जारी कर रहा है, यह पहलू एसबीआई के लिए ठीक नहीं है, इसका उसके ग्राहकों के बीच बेहद प्रतिकूल संदेश जा रहा है। तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। बेशक, देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को पारदर्शिता का परिचय देते हुए अपनी साख बनाए रखनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि वह प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ के आदेश का अक्षरशः पालन करे। इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत ही चुनावी चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए की गई थी और एसबीआई पर भरोसा किया गया था। अतः अब एसबीआई का दायित्व है कि वह इस भरोसे पर खरा उतरकर दिखाए। उसकी ओर से जब सारी सूचनाएं सामने आ जाएंगी, तब लोग यह परखने की स्थिति में होंगे कि अरबों के चंदे का लेन-देन कैसे सुलभ हुआ? राजनीतिक चंदा कतई अनैतिक नहीं है, पर उसमें पारदर्शिता का होना जरूरी है। बीत गए वे दिन, जब चंदे गोपनीय हुआ करते थे। चुनावों में काले धन का खूब प्रयोग हुआ करता था, पर आज के सूचना प्रधान दौर में लोगों की जिज्ञासाओं का समाधान कम से कम एक लोकतांत्रिक देश में होना ही चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जहां एसबीआई कठघरे में है, वहीं राजनीतिक पार्टियों की भी एक जिम्मेदारी बनती है। क्या राजनीतिक पार्टियां स्वयं आगे बढ़कर यह नहीं बता सकतीं कि उन्हें कब किसने कितना चंदा दिया? इधर, केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है, पर राज्यों में सत्तारूढ़ कुछ पार्टियों के जवाब हैरान करने के लिए पर्याप्त हैं। कुछ पार्टियों की ओर से यह जवाब आया है कि उन्हें पता ही नहीं कौन चंदा दे गया? क्या ऐसे जवाब पर विश्वास कर लेना चाहिए? कायदा तो यही बोलता है कि राजनीतिक पार्टियों को सूचना के अधिकार के दायरे में आना चाहिए, पर ऐसी कोशिश को पार्टियां पहले खारिज कर चुकी हैं। शायद एक दिन आएगा, जब राजनीतिक पार्टियां स्वयं ही लोगों को पर्याप्त सूचनाएं मुहैया कराने लगेंगी और किसी भी नागरिक को सूचना के लिए अदालत जाने की नौबत नहीं आएगी।

(विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च पर विशेष)

हमारी पर्यावरण दोस्त है चुलबुली गौरैया

हमारी सोच अब आहिस्ता-आहिस्ता बदलने लगी है। हम प्रकृति और जीव-जंतुओं के प्रति थोड़ा मित्रवत भाव रखने लगे हैं। घर की टेरेस पर पक्षियों के लिए दाना-पानी डालने लगे हैं। गौरैया से हम फ्रेंडली हो चले हैं। किचन गार्डन और घर की बालकनी में कृतिम घोंसला लगाने लगे हैं। गौरैया धीरे-धीरे हमारे आसपास आने लगी है। उसकी चीं-चीं की आवाज हमारे घर आंगन में सुनाई पड़ने लगी है। गौरैया संरक्षण को लेकर ग्लोबल स्तर पर बदलाव आया है। यह सुखद है। फिर भी अभी यह नाकाफी है। हमें प्रकृति से संतुलन बनाना चाहिए। हम प्रकृति और पशु-पक्षियों के साथ मिलकर एक सुंदर प्राकृतिक वातावरण तैयार कर सकते हैं। जिन पशु-पक्षियों को हम अनुपयोगी समझते हैं, वह हमारे लिए प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित करने में अच्छी खासी भूमिका निभाते हैं, लेकिन हमें इसका ज्ञान नहीं होता।

गौरैया हमारी प्राकृतिक मित्र है और पर्यावरण में सहायक है। गौरैया प्राकृतिक सहचरी है। कभी वह नीम के पेड़ के नीचे फुदकती और चावल या अनाज के दाने को चुगती है। कभी घर की दीवार पर लगे आईने पर अपनी हमशक्ल पर चोंच मारती दिख जाती है। एक वक्त था जब बबूल के पेड़ पर सैकड़ों की संख्या में घोंसले लटके होते थे, लेकिन वक्त के साथ गौरैया एक कहानी बन गई। हालांकि पर्यावरण के प्रति जागरुकता के चलते हाल के सालों में यह दिखाई देने लगी है। गौरैया इंसान की सच्ची दोस्त भी है और पर्यावरण संरक्षण में उसकी खासी भूमिका भी है। दुनिया भर में 20 मार्च गौरैया संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी गौरैया संरक्षण के लिए लोगों से पहल कर चुके हैं। उन्होंने राज्यसभा सदस्य बृजलाल के प्रयासों को को सोशल मीडिया में खूब सराहा था और कहा था

कि गौरैया संरक्षण को लेकर आपका प्रयास बेहतरीन और काबिल-ए-तारीफ है। राज्यसभा सदस्य बृजलाल ने अपने घर में गौरैया संरक्षण को लेकर काफी अच्छे उपाय किए हैं। उन्होंने गौरैया के लिए दाना-पानी और घोंसले की व्यवस्था की है। जंगल में आजकल पंच सितारा संस्कृति विस्तार ले रही है। प्रकृति के सुंदर स्थान को भी इंसान कमाने का जरिया बना लिया है। जिसकी वजह पशु- पक्षियों के लिए खतरा बन गया है।

प्रसिद्ध पर्यावरणविद् मोहम्मद ई. दिलावर के प्रयासों से 20 मार्च को चुलबुली गौरैया के लिए रखा गया। 2010 में पहली बार यह दुनिया में मनाया गया। गौरैया का संरक्षण हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इनसान की भोगवादी संस्कृति ने हमें प्रकृति और उसके साहचर्य से दूर कर दिया है। गौरैया एक घरेलू और पालतू पक्षी है। यह इंसान और उसकी बस्ती के पास अधिक रहना पसंद करती है। पूर्वी एशिया में यह बहुतायत पाई जाती है। यह अधिक वजनी नहीं होती। इसका जीवनकाल दो साल का होता है। यह पांच से छह अंडे देती है।

भारत की आंध्र यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में गौरैया की आबादी में 60 फीसदी से अधिक की कमी बताई गई है। ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन आफ बर्ड्स ने इस चुलबुले और चंचल पक्षी को रेड लिस्ट में डाल दिया है। दुनिया भर में ग्रामीण और शहरी इलाकों में गौरैया की आबादी घटी है। गौरैया की घटती आबादी के पीछे मानव विकास सबसे अधिक जिम्मेदार है। गौरैया पासेराडेई परिवार की सदस्य है लेकिन इसे वीवरपिंच परिवार का भी सदस्य माना जाता है। इसकी लंबाई 14 से 16 सेंटीमीटर होती है। इसका वजन 25 से 35 ग्राम तक होता है। यह अधिकांश झुंड में रहती है। यह अधिकतम दो मील की दूरी तय करती है। मानव जहां-जहां गया, गौरैया उसका हमसफर बनकर उसके साथ गई। गांवों में अब पक्के मकान बनाए जा रहे हैं। जिसका कारण है कि मकानों में गौरैया को अपना घोंसला बनाने के लिए सुरक्षित जगह नहीं मिल रही है। पहले गांवों में कच्चे मकान बनाए जाते थे। उसमें लकड़ी और दूसरी वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता था। कच्चे मकान गौरैया के लिए प्राकृतिक वातावरण और तापमान के लिहाज से अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराते थे, लेकिन आधुनिक मकानों में यह सुविधा अब उपलब्ध नहीं होती। यह पक्षी अधिक तापमान में नहीं रह सकता। देश की खेती-किसानी में रासायनिक उर्वरकों का बढ़ता प्रयोग बेजुबान पक्षियों और गौरैया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। केमिकल युक्त रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग से कीड़े-मकोड़े भी विलुप्त हो चले हैं। जिनमें गिद्ध, कौआ, महोख, कठफोड़वा, और गौरैया शामिल हैं। इनके भोजन का भी संकट खड़ा हो गया है। प्रसिद्ध पर्यावरणविद् मोहम्मद ई. दिलावर नासिक से हैं और वह बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी से जुड़े रहे हैं। उन्होंने यह मुहिम 2008 से शुरू की थी। आज यह दुनिया के 50 से अधिक मुल्कों तक पहुंच गई है। दिलावर के विचार में गौरैया संरक्षण के लिए लकड़ी के बुरादे से छोटे-छोटे घर बनाए जाएं और उसमें खाने की भी सुविधा भी उपलब्ध हो। घोंसले सुरक्षित स्थान पर हों, जिससे गौरैयों के अंडों और चूजों को हिंसक पक्षी और जानवर शिकार न बना सकें। हमें प्रकृति और जीव-जंतुओं के सरोकार से लोगों को परिचित कराना होगा। आने वाली पीढ़ी तकनीकी ज्ञान अधिक हासिल करना चाहती है, लेकिन पशु-पक्षियों से वह जुड़ना नहीं चाहती है। इसलिए हमें पक्षियों के बारे में जानकारी दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए, जिससे हम अपनी पर्यावरण दोस्त को उचित माहौल दे पाएं।

भारत में जल संकट- कितना है और हम क्या कर सकते हैं?

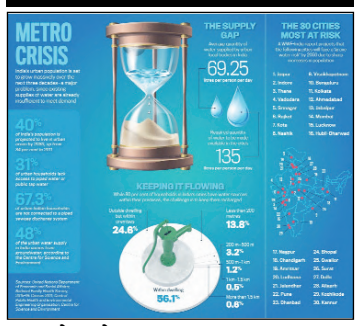

शेष पेज 1 का....

क्या आप जानते हैं कि त्वरित बाल्टी स्नान के बजाय ओवरहेड शॉवर और लंबे समय तक स्नान करने से आपकी त्वचा तेजी से सूखती है और एक्जिमा की गंभीरता बढ़ जाती है? बाल्टी और मग का उपयोग करें एक्जिमा को रोकें और पानी बचाएं

नलों पर एरेटर लगाएं 30 मिनट के बर्तन धोने के सत्र में अब 990 लीटर की खपत होती है जबकि पहले 9450 लीटर की खपत होती थी। यह दिन भर के छोटे बर्तनों के लिए है। दिन के अंत में फुल लोड के लिए - डिशवॉशर का उपयोग किया जाता है जो मैन्युअल धुलाई की तुलना में अधिक पानी कुशल है, लगभग बचत 360 लीटर। आरो से सारा अपशिष्ट जल एक कंटेनर में एकत्र किया जा रहा है और इस पानी का उपयोग पोछा लगाने और बगीचे में उपयोग के लिए किया जाता है। अनुमानित बचत 30 लीटर **अन्य**-वॉशिंग मशीन का उपयोग पूर्ण लोड प्राप्त होने पर किया जाता है। कार धोना बंद कर दिया गया है-हर दिन धूल झाड़ना और दूसरे दिन गीले कपड़े से सफाई करना-कार अभी भी चमकती है! सिंगल पुश फ्लश उपयोग प्लंबर से किसी भी पाइप लीकेज का ऑडिट करने के लिए कहा गया, लगभग बचत 30 लीटर।

मोहन यादव को स्वयं भरोसा नहीं था कि वह मुख्यमंत्री बनेंगे....

महाकाल लोक में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ-डॉ. यादव

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि उन्हें खुद पता नहीं था कि भाजपा का एक साधारण कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा। भोपाल में भाजपा नेता चयन का मामला चल रहा था। तब मैं अपने मित्र अशोक रोहानी के पास अंतिम पंक्ति में बैठे थे।

मैं उनसे इधर-उधर की बात करता रहा। आगे की पंक्ति में हमारे बड़े और वरिष्ठ नेता बैठे थे। उनमें से किसी एक का नेता बनना तय था। उस समय कई नेताओं के चेहरों पर खुशी झलक रही थी...और विश्वास था कि उनमें से ही किसी एक का भाजपा नेता के रूप में चयन किया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहनलाल खट्टर मौजूद थे...और स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके नाम (मोहन यादव) की घोषणा की....तब भी मैं रोहानी से बातचीत करता रहा...और यह अप्रत्याशित था कि उनका नाम कैसे आए....मेरे नाम को दुबारा पुकारा गया तो तब भी मैं बातचीत में लगा रहा....मैं अपने स्थान से नहीं उठा....क्योंकि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था....जब मुझे संकेत दिया गया तो मैं अपने स्थान से उठा।

आज तक टीवी के एक इंटरव्यू में डॉ. यादव ने कहा कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो कि एक साधारण कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना सकती हैं। साक्षात्कार के दौरान पूछे गए कई प्रश्नों के उत्तर में कहा कि मैंने मुख्यमंत्री पद के लिए कोई लाबिंग नहीं की... और ना ही कोई पहल की....उनका कहना था कि कार्यकर्ता आधारित पार्टी होने के कारण हम अपना नाम आगे भी नहीं ला सकते.... यदि लाते भी है तो पार्टी उसे कभी स्वीकार नहीं करती.... यही नहीं उस पद पर कभी बन भी नहीं सकते।

उन्होंने कहा कि उनमें क्या विशेषता थी। यह मुझे पता नहीं था.... हां....हमारे वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता का काम देखते हैं....और उन पर उनकी निगाह रहती है... उसी आधार पर ही चयन होता है.....उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मैंने होटल चलाई है.... साधारण परिवार की तरह जीवन जिया है....उन्होंने पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि महाकाल लोक के निर्माण में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है....जिस पार्टी को महाकाल लोक में मूर्ति निर्माण का कार्य दिया गया था.....उसके अनुबंध/शर्तों में उन्हें ठीक करने का अनुबंध भी था.... आंधी/तूफान से क्षतिग्रस्त हुई मूर्तियों को शर्तों के मुताबिक पुनः लगाया गया है...उन्होंने कहा कि इसी आंधी/तूफान में एक कांग्रेसी नेता का वेयरहाउस भी क्षतिग्रस्त हो गया था।

डॉ. यादव ने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि भाजपा में आने वालों में कांग्रेस की लंबी लाइन लगी है....उन्हें किसी ईडी/एजेंसी के भय से भाजपा में नहीं लाया गया है....उनका कहना था कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा के पीछे-पीछे कांग्रेस के लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। डॉ. यादव ने आज तक टीवी चैनल द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब बड़ी बेबाकी के साथ जवाब दिए।

लघुकथा...

बुजुर्गों का सम्मान करें यह हमारी धरोहर

बुजुर्ग पिताजी जिद कर रहे थे कि, उनकी चारपाई बाहर बरामदे में डाल दी जाये। बेटा परेशान था...बहू बड़बड़ा रही थी....। कोई बुजुर्गों को अलग कमरा नहीं देता, हमने दूसरी मंजिल पर कमरा दिया.... AC TV FRIDGE सब सुविधाएं हैं, नौकरानी भी दे रखी है। पता नहीं, सत्तर की उम्र में सठिया गए हैं..?

पिता कमजोर और बीमार हैं....जिद कर रहे हैं, तो उनकी चारपाई गैलरी में डलवा ही देता हूँ, निकित ने सोचा। पिता इच्छा की प्री करना उसने स्वभाव बना लिया था।

अब पिता की एक चारपाई बरामदे में भी आ गई थी। हर समय चारपाई पर पडे रहने वाले पिता अब टहलते टहलते गेट तक पहुंच जाते। कुछ देर लान में टहलते लान में नाती-पोतों से खेलते, बातें करते, हंसते, बोलते और मुस्कुराते। कभी-कभी बेटे से मनपसंद खाने की चीजें भी लाने की फरमाईश भी करते। खुद खाते, बहू-बेटे और बच्चों को भी खिलाते....धीरे-धीरे उनका स्वास्थ्य अच्छा होने लगा था।

दादा! मेरी बाल फेंको। गेट में प्रवेश करते हुए निकित ने अपने पाँच वर्षीय बेटे की आवाज सुनी, तो बेटा अपने बेटे को डांटने लगा...अंशुल बाबा बुजुर्ग हैं, उन्हें ऐसे कामों के लिए मत बोला करो।

पापा! दादा रोज हमारी बॉल उठाकर फेंकते हैं....अंशुल भोलेपन से बोला।

क्या... निकित ने आश्चर्य से पिता की तरफ देखा?

पिता-हां बेटा तुमने ऊपर वाले कमरे में सुविधाएं तो बहुत दी थीं। लेकिन अपनों का साथ नहीं था। तुम लोगों से बातें नहीं हो पाती थी। जब से गैलरी मे चारपाई पड़ी है, निकलते बैठते तुम लोगों से बातें हो जाती है। शाम को अंशुल-पाशी का साथ मिल जाता है।

पिता कहे जा रहे थे और निकित सोच रहा था.....बुजुर्गों को शायद भौतिक सुख सुविधाओं से ज्यादा अपनों के साथ की जरूरत होती है....।

बुजुर्गों का सम्मान करें यह हमारी धरोहर हैं और अपने बुजुर्गों का खयाल हर हाल में अवश्य रखें...यह वो पेड़ हैं, जो थोड़े कड़वे है, लेकिन इनके फल बहुत मीठे है, और इनकी छांव का कोई मुकाबला नहीं।

संकलन-सुधीर उपाध्याय

शिव-पार्वती की शादी का रिसेप्शन

उज्जैन। महाशिवरात्रि का पर्व वैसे तो पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन महाकाल की नगरी उज्जैन में इसका एक अलग ही महत्व है। माता की नवरात्रि की तरह उज्जैन में 9 दिनों तक महाशिवरात्रि मनाई जाती है और 9 दिनों तक महाकाल का हर दिन एक नया श्रृंगार किया जाता है।

महाशिवरात्रि के आखिरी दिन बाबा महाकाल को सेहरा चढ़ता और साल में एक बार दिन में भस्मारती होता है। उज्जैन की महाकाल नगरी में वैसे तो महाशिवरात्रि 8 मार्च को हो चुकी है और अब विवाह के बाद रिसेप्शन का आयोजन किया जा रहा है। उज्जैन में यह आयोजन हर साल महाकाल शयन आरती भक्त मंडल की ओर से किया जाता है। इस बार उनका यह 24वां आयोजन है। महाशिवरात्रि के बाद शिव-पार्वती विवाह का रिसेप्शन किया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा शहर के लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। महाकाल शयन आरती भक्त मंडल द्वारा लोगों के घर-घर पहुंच कर विवाह के कार्ड देकर उन्हें आमंत्रित किया जा रहा है। कार्ड में विवाह का पूरा कार्यक्रम बताया गया है। सोमवार सुबह शिव विवाह की रस्म के बाद महाकाल को शाम हल्दी लगाई गई और मेहंदी और महिला संगीत का कार्यक्रम हुआ। निमंत्रण कार्ड में देवता स्वागतातुर और दर्शन अभिलाषी में भगवान गणेश, रिद्धि, सिद्धि और शिव परिवार लिखा गया है। इसके अलावा 33 करोड़ देवी लिखा गया है। वहीं मंगलवार 19 मार्च को बारात और रिसेप्शन रखा गया है। पूरे शहर को आमंत्रित किया गया है। खास बात यह है कि कार्यक्रम रामघाट के पास महाकाल मंडपम में होगा। मंगलवार को नगर कोट के गणेश्वर महादेव मंदिर से शिव बारात निकलेगी। यहां से बारात महाकाल मंडपम तक पहुंचेगी। बारातियों के स्वागत के लिए इंतजाम किए गए हैं। साफा बांधने वाले से लेकर जूते साफ करने वाले, शेविंग बनाने वाले, कपड़े प्रेस करने वाले के भी इंतजाम किए गए हैं। बारात के लिए दो बैंड और ढोल किए गए हैं। नगर भोज में 40 से 50 हजार भक्तों के आने की उम्मीद है। महाकाल शयन आरती भक्त मंडल की ओर से घर-घर जाकर निमंत्रण दिया गया है। रिसेप्शन के मेन्यू में सब्जी, पूरी, पुलाव, खीर, खोपरा पाक के साथ गन्ने का रस, शिकंजी, लस्सी, पानी पतासे और पान भी खाने को मिलेगा।

70 डिब्बे तेल, 40 क्विंटल आटा, 10 क्विंटल आलू , 4 क्विंटल टमाटर, डेढ़ क्विंटल मटर, 5 क्विंटल का पुलाव, 10 क्विंटल गन्ना, 5 क्विंटल दही और दूसरा जरूरी सामान कार्यक्रम स्थल तक पहुंच चुका है।

संघ क्या हैं जान लीजिए?

भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना ही संघ का मुख्य लक्ष्य

गत दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक नागपुर में दिनांक 15 से 17 मार्च 2024 को सम्पन्न हुई है। इस बैठक में पूरे देश से 1500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया और श्रीराम मंदिर से राष्ट्रीय पुनरुत्थान की ओर विषय पर एक प्रस्ताव भी पास किया गया। जैसा कि सर्वविदित ही है कि गौरवशाली हिन्दू सनातन संस्कृति विश्व में सबसे पुरानी संस्कृति मानी जाती है और इसी हिंदू सनातन संस्कृति का अनुपालन करते हुए भारत का इतिहास वैभवशाली रह पाया है तथा हिंदू सनातन संस्कृति का विस्तार इंडोनेशिया तक एवं सुदूर अमेरिका तक रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में अक्सर यह कहा जाता है कि संघ एवं इसके स्वयंसेवक करते क्या हैं? इसके उत्तर में अक्सर यह जवाब दिया जाता है कि संघ को यदि समझना है तो आपको संघ की शाखा में आना होगा। संघ, मां भारती को एक बार पुनः विश्व में गौरवशाली स्थान दिलाने के पवित्र लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गम्भीर प्रयास कर रहा है। इस पवित्र लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लाखों की संख्या में स्वयंसेवक आज संघ के साथ जुड़ चुके हैं।

आज भारत के 45,600 स्थानों पर संघ की 73,117 शाखाएं, 27,717 साप्ताहिक मिलन एवं 10,567 संघ मंडली लगाई जा रही हैं। इन शाखाओं, साप्ताहिक मिलनों एवं संघ मंडलियों में स्वयंसेवकों में राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव (राष्ट्र प्रथम) जागृत किया जाता है। ताकि वे समाज में जाकर समाज की सज्जन शक्ति को साथ लेकर भारत में समाज परिवर्तन का कार्य दक्षतापूर्वक कर सकें।

संघ की शाखा सामान्यतः 60 मिनट की लगती है एवं इसमें शारीरिक व्यायाम, योग, प्राणायाम, खेल, बौद्धिक एवं प्रार्थना शामिल रहती है।

बौद्धिक में सनातन संस्कृति एवं भारत के गौरवशाली इतिहास की जानकारी के साथ साथ भारतीय संतो, महात्माओं एवं महापुरुषों की जानकारी प्रदान की जाती है समय के साथ साथ संघ ने अपनी कार्यप्रणाली में परिवर्तन भी किया है एवं कई नए आयाम एवं कार्य अपने साथ जोड़े हैं। जैसे समाज के किन किन क्षेत्रों में क्या क्या काम करना है यह संघ के स्वयंसेवकों को बहुत स्पष्ट रूप से सिखाया जाता है।

संगठन श्रेणी के साथ ही संघ में जागरण श्रेणी भी कार्यरत है। संगठन श्रेणी में शाखाओं के विस्तार, इसे सुचारू रूप से चलाने सम्बंधी कार्य, स्वयसेवकों का प्रशिक्षण एवं गुणवत्ता विकास आदि कार्य शामिल रहते हैं जबकि ्रजागरण्ड्श्रेणी में समाज में जाकर किन क्षेत्रों में जागरण करना है, का निर्धारण किया जाकर इस क्षेत्र में स्वयसेवकों द्वारा कार्य किया जाता है।

जैसे वर्तमान में जागरण श्रेणी में शामिल कार्य हैं-सेवा कार्य(सेवा विभाग), सम्पर्क (संपर्क विभाग) का कार्य एवं प्रचार(प्रचार विभाग-संघ के विचार का प्रचार) सम्बंधी कार्य। इसके अलावा 6 गतिविधियां भी हैं जो स्वयसेवकों द्वारा समाज के सहयोग से चलाई जाती हैं।

इनमे शामिल हैं -

*** धर्म जागरण समन्वय,**
*** गौ सेवा,**
*** ग्राम विकास,**
*** कुटुंब प्रबोधन,**
*** सामाजिक समरसता,**
*** एवं पर्यावरण संरक्षण।**

22 जनवरी 2024 को अयोध्या धाम में प्रभु श्रीराम के भव्य मंदिर में श्रीराम लला के श्रीविग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व दिनांक 1 से 15 जनवरी 2024 तक श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र के आह्वान पर संघ के स्वयंसेवकों एवं समाज के विविध संस्थानों तथा संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा चलाया गया गृह सम्पर्क अभियान अभूतपूर्व सफल रहा था। देश के समस्त प्रांतों के 578,778 गांवों एवं 4727 नगरों के कुल 19.38 करोड़ से अधिक परिवारों से स्वयंसेवकों सहित 44.98 लाख से अधिक व्यक्तियों ने सम्पर्क किया था।

यह भारतीय समाज में संघ की गहरी पहुंच और समाज में उसकी स्वीकार्यता को दर्शाता है। संघ के 40 से अधिक अनुशांगिक संगठन भी भारत में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं, जो हिंदू सनातन संस्कृति एवं भारतीय परम्पराओं के आधार पर समाज में अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं। विश्व में वामपंथी विचारधारा के आधार पर चल रहे विभिन्न मजदूर संगठन अपने श्रमिक सदस्यों को संस्थान के केवल लाभ में हिस्सा लेने की प्रेरणा देते हैं और अपनी मजदूरी में वृद्धि के लिए अक्सर हड़ताल आदि का सहारा लेते हैं। उद्योग संस्थान में हड़ताल होने से न केवल उस विशेष उद्योग संस्थान का बल्कि देश की अर्थव्यवस्था का भी नुक्सान होता है। जबकि, भारतीय मजदूर संघ, जो कि संघ का ही एक अनुशांगिक संगठन है, अपने श्रमिक सदस्यों को हड़ताल करने के लिए निरुत्साहित करता है और उसका नारा है कि-

'संस्थान के लिए करेंगे पूरा काम और काम के लेंगे पूरे दाम'।

यह अंतर है वामपंथी विचारधारा और राष्ट्रीय विचारधारा के संगठनों में। इसी प्रकार संघ के अन्य अनुशांगिक संगठनों में शामिल हैं

(1) सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाले संगठन

- आरोग्य भारती,
- राष्ट्रीय सेवा भारती,
- भारत विकास परिषद,
- राष्ट्रीय चिकित्सा संस्थान,
- सक्षम (दिव्यांग नागरिकों के लिए),
- दीन दयाल शोध संस्थान।

(2) सामाजिक संगठन

- विश्व हिंदू परिषद,
- वनवासी कल्याण आश्रम,
- जनजाति सुरक्षा मंच,
- क्रीड़ा भारती,
- राष्ट्रीय सेविका समिति।

(3) शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले संगठन

- विद्या भारती,
- अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद,
- भारतीय शिक्षण मंडल,
- अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ,
- संस्कृत भारती,
- शिक्षा संस्कृत उत्थान न्यास।

(4)आर्थिक क्षेत्र में कार्य करने वाले संगठन

- भारतीय किसान संघ,
- लघु उद्योग भारती,
- भारतीय मजदूर संघ,
- स्वदेशी जागरण मंच,
- सहकार भारती,
- ग्राहक पंचायत।

(5) वैचारिक समूह में कार्य करने वाले संगठन

- प्रज्ञा प्रवाह,
- विज्ञान भारती,
- संस्कार भारती,
- इतिहास संकलन,
- साहित्य परिषद,
- अधिवक्ता परिषद।

(6) सुरक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले संगठन

- सीमा जागरण मंच,
- हिंदू जागरण मंच,
- अखिल भारतीय रक्षा परिषद।
- उक्त समस्त संगठनों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदत्त है एवं संघ की ओर से किसी भी प्रकार का बंधन इन संगठनों पर नहीं रहता है।
- हां, इन संगठनों की कार्य प्रणाली को भारतीय संस्कारों के अनुरूप ढालना आवश्यक रहता है।

अपने आचरण, आचार विचार एवं कार्य पद्धति के आधार पर भारतीय मूल के नागरिक हिंदू सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में अन्य कई देशों में कार्यरत हैं एवं वहां निवास कर रहे हैं और इन देशों की अर्थव्यवस्था में अपने योगदान को दिनोदिन मजबूती प्रदान कर रहे हैं। इन देशों के विभिन्न क्षेत्रों यथा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि में भारतवंशियों के योगदान को इन देशों मूल नागरिकों ने पहचाना एवं स्वीकारा है। इसके चलते लाखों की संख्या में विदेशी मूल के नागरिक हिंदू सनातन संस्कृति की ओर आकर्षित हुए हैं एवं अब ऐसा माना जाने लगा है कि हिंदू सनातन संस्कृति पूरे विश्व में भविष्य का विश्व धर्म होने जा रही है।

- अतः आज विश्व के 53 देशों में हिंदू स्वयंसेवक संघ की स्थापना की जा चुकी है एवं
- इन देशों में 1480 शाखाएं एवं 112 मिलन चलाए जा रहे हैं।
- हाल ही में आस्ट्रेलिया एवं अमेरिका के कई नगरों में संघ शिक्षा वर्ग आयोजित किए गए थे तथा इसी प्रकार
- विश्व के अन्य देशों को मिलाकर कुल 17 हिंदू हेरिटेज कैम्प भी आयोजित किए गए थे।
- अमेरिका में सेवा दीवाली बहुत धूमधाम से मनाई जाती है,
- इस शुभ मौके पर स्थानीय गरीब वर्ग को उपहार प्रदान किए जाते हैं। पूरे विश्व में आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को विश्व का सबसे बड़ा संगठन माना जाता है जो पिछले 99 वर्षों से सतत रूप से हिंदू सनातन संस्कृति एवं भारतीय परम्पराओं तथा संस्कारों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए मां भारती की सेवा में अपने आप को समर्पित किए हुए है। आज समाज की ससज्जन शक्ति संघ की विचारधारा के अनुरूप सोचने लगी है।

अतः विभिन्न श्रेणी विशेष के नागरिक यथा चिकित्सक, शिक्षक, प्रोफेसर, अभिभाषक, श्रमिक, सेवा निवृत्त अधिकारी एवं कर्मचारी, युवा उद्यमी आदि बड़ी संख्या में संघ के साथ जुड़ रहे हैं एवं समाज परिवर्तन में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं।

आज भारत में विभिन्न मत पंथ को मानने वाले नागरिकों के बीच यदि आपस में भाईचारा स्थापित होता है तो निश्चित ही मां भारती को उसके पुराने वैभव को प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता है।

उज्जैन व आलोट विधानसभा के संसदीय क्षेत्र में 8 फरवरी 2024 की स्थिति में 17,72,734 मतदाता हैं, जिसमें 8,95,392 पुरुष, 8,77,267 महिलाएं एवं 75 अन्य शामिल हैं

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन की घोषणा के साथ ही उज्जैन जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई हैं। इसके तहत अब 18 अप्रैल से 25 अप्रैल तक नाम निर्देशन पत्र जमा होंगे, 26 अप्रैल को जांच होगी। 29 अप्रैल तक नाम वापसी, 13 मई को मतदान और 4 जून को मतगणना होगी।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उज्जैन नीरज कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि लोकसभा निर्वाचन की अधिसूचना का प्रकाशन 18 अप्रैल 2024 को किया जाएगा। अधिसूचना के प्रकाशन के साथ ही अभ्यर्थियों से नामांकन पत्र जमा करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा अंतिम तिथि 25 अप्रैल तक अपना नामांकन पत्र जमा कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की संविक्षा 26 अप्रैल को की जाएगी। नामांकन पत्र वापसी की अंतिम तिथि 29 अप्रैल रहेगी। उज्जैन जिले में 13 मई को मतदान किया जाएगा। मतगणना 4 जून को इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन में की जाएगी। कलेक्टर सिंह ने बताया कि 13 मई को उज्जैन संसदीय क्षेत्र में 2077 मतदान केंद्रों पर मतदान किया जाएगा। इसमें प्रमुख रूप से विधानसभा नागदा खाचरोद में 271, महिदपुर में 262, तराना में 238 ,घट्टिया में 279, उज्जैन उत्तर में 257, उज्जैन दक्षिण में 285, बड़नगर में 232 एवं आलोट में 253 मतदान केंद्र शामिल हैं। जिले में अभी तक 310 क्रिटिकल मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं। 2077 मतदान केंद्रों के लिए कुल 209 सेक्टर ऑफिसर बनाए गए हैं।

17,72,734 मतदाता करेंगे मतदान

उज्जैन व आलोट विधानसभा के संसदीय क्षेत्र में 8 फरवरी 2024 की स्थिति में 17,72,734 मतदाता हैं, जिसमें 8,95,392 पुरुष, 8,77,267 महिलाएं एवं 75 अन्य शामिल हैं। उज्जैन के मतदाताओं जेंडर रेशो 980 है और सर्विस वोटर की संख्या 1643 हैं।

29 एफएसटी, 38 एसएसटी एवं 17 चेक पोस्ट पर होगी चेकिंग

आदर्श आचरण संहिता का प्रभावी ढंग से क्रियान्वन करने के लिए 29 एफएसटी एवं 28 एसएसटी दल (स्थैतिक निगरानी दल) का गठन किया जाएगा, जो 18 अप्रैल से सक्रिय होगी। सीमाओं पर 17 चेक पोस्ट पर आज से चेकिंग शुरू हो जाएगी।

85 प्लस आयु के 12,724 मतदाता, 13,097 पीडब्ल्यूडी वोटर्स

उज्जैन लोकसभा संसदीय क्षेत्र में 85 प्लस आयु के मतदाताओं की संख्या 12724 है, जिनमें 3931 पुरुष एवं 8793 महिलाएं शामिल हैं। पीडब्ल्यूडी वोटर्स 13097 हैं, जिन्हें 12 डी का आवेदन जमा करने पर घर पर मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

24×7 सतत कार्य करेगा कन्ट्रोल रूम

जिला स्तर पर कन्ट्रोल रूम नवीन प्रशासनिक संकुल भवन के प्रथम तल स्थित कक्ष क्रमांक 123 पर स्थापित किया गया है। विनीता रॉय, सहायक संचालक कृषि (मो.-9926464057) कंट्रोल रूम की प्रभारी रहेगी। कन्ट्रोल रूम 24×7 सतत् कार्य करेगा। कंट्रोल रूम के नंबर 0734-2527410, 2527411, 2527412, 2527413, 2527414 रहेंगे।

प्रतिबंधात्मक आदेश लागू

आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन के लिए कार्यक्रम घोषित करने के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। इसके साथ ही जिले में धारा 144 लागू किये जाने से प्रतिबंधात्मक आदेश भी प्रभावी हो गए हैं। जिले में शस्त्र लायसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। लायसेंस धारकों से उनके शस्त्र निकटतम पुलिस थाने में जमा कराने की कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है। अब जिले में अस्त्र शस्त्रों के परिवहन व प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। होटल, सराय, धर्मशालाओं में रुकने वाले यात्रियों की जानकारी होटल संचालकों को निकटतम थाने में देना अनिवार्य होगी।

संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई

लोकसभा निर्वाचन के मद्देनजर मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम का सख्ती से पालन कराया जाएगा। इस अधिनियम के तहत संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बगैर सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी भी संपत्ति को विरूपित करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

सी-विजिल एप या दूरभाष पर कर सकते हैं शिकायत

लोकसभा निर्वाचन के दौरान कोई भी व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया में अनियमितता संबंधी शिकायत ''सी-विजिल'' एप के माध्यम से दर्ज करा सकता है। इस एप में आवेदक को शिकायत संबंधी फोटो अथवा वीडियो उसकी लोकेशन के साथ अपलोड करने की सुविधा भी उपलब्ध है। निर्वाचन आयोग के दूरभाष क्रमांक 1950 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। वहीं निर्वाचन संबंधी शिकायतों के निराकरण के लिए जिला स्तर पर शिकायत प्रकोष्ठ स्मार्ट सिटी कार्यालय पर स्थापित किया गया है। धीरेन्द्र पाराशर डिप्टी कलेक्टर (मो.-9425364166) प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी एवं आरपीएस नायक उप संचालक कृषि सहायक नोडल अधिकारी रहेंगे। जिला कांटेक्ट सेंटर का नंबर 1950 है। उक्त सेंटर नवीन प्रशासनिक संकुल भवन के प्रथम तल स्थित कक्ष कमांक 129 पर स्थापित किया गया है।

कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सैयद जाफर समेत 68 से ज्यादा कांग्रेस-बसपा नेता भाजपा में शामिल

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, पार्टी के लोकसभा चुनाव के सह प्रभारी सतीष उपाध्याय एवं न्यू ज्वॉइनिंग टोली के प्रदेश संयोजक डॉ. नरोत्तम मिश्रा के समक्ष प्रदेश कार्यालय में सोमवार को कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सैयद जाफर, पथरिया के वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिनेश श्रीधर, कांग्रेस महामंत्री डॉ. मनीषा दुबे, रतलाम जिला पंचायत सदस्य संतोष पालीवाल, बसपा के प्रदेश प्रभारी व प्रदेश महासचिव डॉ. रामसखा वर्मा, पूर्व प्रचारक अभयराज सिंह, रतलाम के मध्यप्रदेश आईटी सेल महामंत्री अंकित पोरवाल, जिला कांग्रेस कमेटी महामंत्री विरेन्द्र नायमा, आलोट विधानसभा युवक कांग्रेस के अध्यक्ष सुरेश डागी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश मैनूखेड़ी, ब्लॉक अध्यक्ष दुर्गालाल अटोलिया, एनएसयूआई के जिला प्रभारी गोपाल सिसोदिया सहित 68 से अधिक जनपद सदस्य, सरपंच, पूर्व सरपंच, कांग्रेस पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं ने भाजपा की विचारधारा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मुख्यमंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष ने अंगवस्त्र पहनाकर उनका स्वागत किया।

इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष चिंतामणि मालवीय, प्रदेश महामंत्री व विधायक भगवानदास सबनानी, प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल, छिंदवाड़ा लोकसभा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू, प्रदेश प्रवक्ता डॉ. सनवर पटेल, मिलन भार्गव एवं अजय धवले उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज छिंदवाड़ा से कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सैयद जाफर सहित कई कांग्रेस नेताओं और बसपा पदाधिकारियों ने पार्टी की विचारधारा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं सभी को विश्वास दिलाता हूं कि जहां-जहां से कार्यकर्ताओं ने पार्टी ज्वाइन की है, वहां-वहां विकास के काम आपके बताने पर किए जाएंगे। रोज प्रधानमंत्री मोदी का परिवार बढ़ रहा और यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है।

डबल इंजन की सरकार में प्रदेश का खूब विकास हुआ है और अब हम सब मिलकर एक साथ काम करके सभी सीटों को जीतेंगे।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि छिंदवाड़ा से कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जाफर ने भी तय किया कि अगर देश में कुछ करना है तो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा में रहकर किया जा सकता है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर सैयद जाफर सहित कई कांग्रेस और बसपा पाधिकारियों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं सभी को शुभकामनाएं देकर विश्वास दिलाता हूं कि पार्टी में उन्हें मान-सम्मान के साथ पार्टी की इस यात्रा में शामिल कर साथ काम किया जाएगा।

शर्मा ने कहा कि प्रदेश के हर बूथ पर ज्वाइनिंग हो रही है। प्रदेश में हर बूथ पर कांग्रेस और अन्य दलों के कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। देशभर में मध्यप्रदेश न्यू ज्वाइनिंग के रिकॉर्ड बना रहा है। हर बूथ पर पहले से 370 अधिक वोट हासिल करने का हमारा लक्ष्य है और हम इस दिशा में तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। प्रतिदिन कांग्रेस या अन्य दलों के नेताओं एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के पार्टी में शामिल होने से हमारी ताकत और बढ़ रही है।

आर्टिस्ट टैलेंट अवॉर्ड शो में नदिया के पार की हीरोइन साधना सिंह ने बांटे 290 अवार्ड

उज्जैन। प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी आर्टिस्ट टैलेंट अवॉर्ड शो का आयोजन किया गया। जिसमें डबल गोल्डन जुबली फिल्म नदिया के पार की हीरोइन साधना सिंह मुंबई ने मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहकर 290 अवार्ड बांटे।

मुख्य संयोजक पूनम लालवानी के नेतृत्व में शर्मा परिसर देवास रोड पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। मीडिया प्रभारी दीपक राजवानी ने बताया कि जिसमें मेकअप आर्टिस्ट सरिता प्रजापति, भारती चौहार, मीनाक्षी गौर, पुर्णिमा व्यास, कान्हा बाबा, रीना खंडेलवाल, संदीप सेन, शिवम तला शामिल हुए।

अतिथि के रूप में राजकुमारी महेश्वरी संगीता शर्मा सुनीता जायसवाल वंदना शर्मा समीक्षा व्यास, प्रतिभा त्रिवेदी, सोनिया सहगल, मीना गुप्ता, पूजा भुजाड़े, सीमा हुसैन, पिंकी अरोरा, रजनी राठौर, सुनीता जायसवाल, प्रमिला ताला, आरती सोनी, वंदना शर्मा, डॉ. कीर्ति श्रीवास्तव, सत्यनारायण, नम्रता जैन, नीलम जाट, वेदेही भार्गव, सोनिया कुडेसिया मौजूद रहे। पार्टिसिपेंट मैं दीपिका शर्मा उपमा दुबे आरती उतरा महक सोनी प्रीति मोरवाल दिव्या यादव गीता तोमर माया शर्मा अनीता बाफना रानी कुमरावत राखी सिसोदिया वर्षा अग्रवाल पूजा सिसोदिया दीपिका चौहान शोभना आदि पार्टिसिपेंट किया कार्यक्रम प्रातः 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक चला जिसमें उज्जैन, रतलाम, इंदौर, शाजापुर, बदनावर, बड़नगर, देवास, सहित अन्य शहरों की 290 ब्यूटीशियनों ने हिस्सा लिया। मॉडलों ने स्टेज प्रोग्राम भी दिया। शहर में प्रथम बार हुए इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मेकअप आर्टिस्टों ने हिस्सा लिया।

उज्जैन जिले में लक्ष्य से अधिक धनराशि का योगदान प्राप्त होने पर राज्यपाल ने कलेक्टर को सम्मानित किया

उज्जैन। सशस्त्र सेना झण्डा दिवस के अवसर पर उज्जैन जिले में लक्ष्य से अधिक धनराशि का योगदान करने पर राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने गत दिवस 11 मार्च को राजभवन में कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह को प्रशंसा पत्र व ट्राफी से सम्मानित किया।

उक्त सम्मान गत दिवस 11 मार्च को राजभवन में कलेक्टर की ओर से जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कमाण्डर श्री नगेशचंन्द्र मालवीय ने ग्रहण किया। प्राप्त प्रशंसा पत्र एवं ट्राफी जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने सोमवार 18 मार्च को टीएल बैठक के दौरान कलेक्टर को भेंट की। उक्त जानकारी जिला सैनिक कल्याण अधिकारी नगेशचन्द्र मालवीय ने बताया कि उज्जैन जिले को सशस्त्र सेना झण्डा दिवस 2022 के लिए 10 लाख 30 हजार का लक्ष्य दिया था, इसके विरूद्ध जिले में 15 लाख 89 हजार 478 रूपये का योगदान प्राप्त हुआ था। यह लक्ष्य राशि का 154 प्रतिशत है। उल्लेखनीय है कि सशस्त्र सेना झण्डा दिवस की सहयोग राशि भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं एवं उनके आश्रित परिवारों की सहायता एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए उपयोग में ली जाती है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने सभी दानदाताओं एवं सहयोग कर्ताओं का आभार प्रकट किया।

केंद्रीय कारागार भैरवगढ़ में पांच दिवसीय आत्म परिष्कार शिविर का शुभारंभ

उज्जैन। मनुष्य जीवन ईश्वर प्रदत्त बहुमूल्य उपहार है। इससे बड़ा उपहार ईश्वर के भंडार में और कोई भी नहीं है। इसमें असीम और दिव्य संभावनाएं भरी पड़ी हैं। अपने जीवन के इस खेत में प्रगति और सफलता की फसल उगाएं।

यह प्रेरक उद्गार देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव जिला समन्वयक उज्जैन ने केंद्रीय कारागार भैरबगढ़ में पांच दिवसीय आत्म परिष्कार शिविर के शुभारंभ सत्र में बंदियों के समक्ष व्यक्त किए। आपने जीवन को उज्जवल, उत्कृष्ट बनाने के लिए स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन और मनन आदि का आश्रय लेने की बात भी बताई। मंत्र विज्ञान की विशिष्ट जानकारियां देते हुए नरेंद्र सिंह सिकरवार ने बताया कि जिस तरह भौतिक उन्नति के लिए यंत्रों की आवश्यकता है उसी प्रकार आत्मिक उन्नति के लिए मंत्र सहायक हैं इसमें कोई संदेह नहीं है। जेल अधीक्षक मनोज साहू ने गायत्री परिवार का शिविर लगाने के लिए आभार व्यक्त किया तथा बंदियों से इसमें पूर्ण मनोयोग पूर्वक भागीदारी कर लाभ लेने का आग्रह भी किया। शिविर की भूमिका रखते हुए जेलर सुरेश गोयल ने बताया कि आत्म परिष्कार शिविर से आप सबके जीवन में सुख शांति आएगी ऐसी हम आशा करते हैं। शिविर में आत्म परिष्कार संबंधित मार्गदर्शन व्याख्यानों के साथ समूह प्रार्थना, मंत्र जाप/लेखन, ध्यान, प्राणायाम, संकीर्तन के प्रयोग भी कराए जा रहे हैं। महिला वार्ड में यही सब क्रम माधुरी सोलंकी एवं नीति टंडन ने कराए, यहां सामूहिक गायत्री चालीसा पाठ भी कराया गया।

देखते ही देखते जवान माँ-बाप बूढ़े हो जाते हैं

देखते ही देखते जवान माँ-बाप बूढ़े हो जाते हैं,
सुबह की सैर में कभी चक्कर खा जाते है,
सारे मौहल्ले को पता है...पर हमसे छुपाते है,
दिन प्रतिदिन अपनी खुराक घटाते हैं और?
तबियत ठीक होने की बात फोन पे बताते है,
ढीली हो गए कपड़ों को टाइट करवाते है,
देखते ही देखते जवान माँ-बाप बूढ़े हो जाते हैं..?
किसी के देहांत की खबर सुन कर घबराते है।
और अपने परहेजों की संख्या बढ़ाते है,
हमारे मोटापे पे हिदायतों के ढेर लगाते है,
रोज की वर्जिश के फायदे गिनाते है,
'तंदुरुस्ती हजार नियामत हर दफे बताते है,
देखते ही देखते जवान माँ-बाप बूढ़े हो जाते हैं,
हर साल बड़े शौक से अपने बैंक जाते है,
अपने जिन्दा होने का सबूत देकर हर्षाते है,
जरा सी बढी पेंशन पर फूले नहीं समाते है,
और FIXED DEPOSIT रिन्ऊ करते जाते है,
खुद के लिए नहीं हमारे लिए ही बचाते है,
देखते ही देखते जवान माँ-बाप बूढ़े हो जाते हैं,
चीजें रख के अब अक्सर भूल जाते है,
फिर उन्हें ढूँढने में सारा घर सर पे उठाते है,
और एक दूसरे को बात बात में हड़काते है,
पर एक दूजे से अलग भी नहीं रह पाते है,
एक ही किस्से को बार बार दोहराते है,
देखते ही देखते जवान माँ-बाप बूढ़े हो जाते है।
चश्में से भी अब ठीक से नहीं देख पाते है,
बीमारी में दवा लेने में नखरे दिखाते है,
एलोपैथी के बहुत सारे साइड इफेक्ट बताते है,
और होमियोपैथी/आयुर्वेदिक की ही रट लगाते है,
जरूरी ऑपरेशन को भी और आगे टलवाते है,
देखते ही देखते जवान माँ-बाप बूढ़े हो जाते हैं,
उड़द की दाल अब नहीं पचा पाते है,
लौकी तुरई और धुली मूंगदाल ही अधिकतर खाते है,
दांतों में अटके खाने को तिली से खुजलाते हैं,
पर डेंटिस्ट के पास जाने से कतराते हैं,
काम चल तो रहा है की ही धुन लगाते है,
देखते ही देखते जवान माँ-बाप बूढ़े हो जाते हैं,
हर त्यौहार पर हमारे आने की बाट देखते है,
अपने पुराने घर को नई दुल्हन सा चमकाते है,
हमारी पसंदीदा चीजों के ढेर लगाते है,
हर छोटी बड़ी फरमाईश पूरी करने के लिए,
माँ रसोई और पापा बाजार दौडे चले जाते है,
पोते-पोतियों से मिलने को कितने आंसू टपकाते है,
देखते ही देखते जवान माँ-बाप बूढ़े हो जाते है,
देखते ही देखते जवान माँ-बाप बूढ़े हो जाते है।

नागरिकता संशोधन कानून पर यूएन-अमेरिका को खुजली हुई

हजारों-लाखों लोगों का वह अह्लादित कर देने वाला रुदन, जो वर्षों से अनवरत न्याय के लिए चीत्कार रहा था। पूछ रहा था कि हमें किस लिए सजा दी गई है? देश का विभाजन तुमने किया, इसमें हमारा क्या दोष था? कहना होगा कि उन सभी की ह्रदय वेदना को कई दशक बीत जाने के बाद अब जाकर न्याय मिला है। भारत में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लागू किया जाना जैसे उनकी वर्षों की तपस्या का परिणाम है। हालांकि इस कानून के लागू होने से यह तो पहले से तय था कि देश में कुछ विरोध के स्वर जरूर उठेंगे, किंतु विदेशों में भी इसके विरोध की होड़ लगेगी, इसका इतना अंदाजा किसी को नहीं था। कम से कम यूएन और अमेरिका से तो यह उम्मीद नहीं की जा सकती थी। आश्चर्य है, यह जानकर कि जिसे भारत और भारत में लागू इस कानून से दूर-दूर तक कोई मतलब नहीं, वह भी भारत की मोदी सरकार और उसके इस निर्णय की

बिना गहराई में जाए आलोचना कर रहे हैं। सबसे ज्यादा संयुक्त राष्ट्र (यूएन) और अमेरिका से शासन स्तर पर आई प्रतिक्रिया परेशान करती हैं। क्यों कि अभी कुछ दिन पहले ही भारत और अमेरिका के बीच होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग (एचएसडी) को पूरा किया गया । इसमें अमेरिका ने भारत की भरपूर प्रशंसा की। यही स्थिति यूएन की है, जहां वह इस बात को कई अवसरों पर स्वीकार्य कर चुका है कि वास्तविक लोकतंत्र और पंथनिरपेक्षता यदि देखनी है तो तमाम विविधताओं के बाद भी एकता के लिए भारत से अच्छा कोई उदाहरण नहीं है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की भी यूएन प्रशंसा कर रहा था।

यूएन भारत की आलोचना तो कर रहा, लेकिन नहीं बता रहा है, कैसे सीएए गलत है। वस्तुतः अब अचानक ऐसा क्या हो गया जो संयुक्त राष्ट्र को लगने लगा है कि भारत का सीएए कानून मौलिक रूप से भेदभावपूर्ण प्रकृति वाला है! आज संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त की ओर से बोला गया है, हम भारत के नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 (सीएए) को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि यह मूल रूप से भेदभावपूर्ण प्रकृति का है। साथ ही यह भारत के अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों का उल्लंघन करता है। अब देखिए , यूएन यहां भारत को इस कानून को लागू करने के लिए कठघरे में तो खड़ा कर रहा है, किंतु यह नहीं बता रहा है कि कैसे भारत का यह नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) किसी के मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है?

क्या संयुक्त राष्ट्र (यूएन) अन्तरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना 78 साल पहले 1945 में इसलिए ही की गई थी कि जो राष्ट्र नियमों का पालन करें, विश्वकल्याण में विश्वास करें, उन्हें दबाते रहना है। फिर वह वैचारिक रूप से हो या किसी अन्य प्रकार से । आज यूएन के कल्याणकारी उद्देश्यों को पढ़कर नहीं लगता है कि वह भारत के संदर्भ में इस तरह का वक्तव्य देगा। देखा जाए तो यूएन आज सीएए पर भारत को घेरने का जो आधार ले रहा है, वह पूरी तरह से अनुचित है। क्योंकि इस कानून को लाने के पीछे जो पृष्ठभूमि रही है, उस पर यूएन को पहले गहन चिंतन एवं शोध करना चाहिए था, फिर जाकर अपनी प्रतिक्रिया देता तो अच्छा रहता । यूएन भूल गया, भारत ने स्वैच्छा से चुनी है पंथ निरपेक्षता।

यूएन को भारत के संदर्भ में यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि स्वाधीन भारत ने अपने लिए लोकतंत्र का रास्ता चुना, जिसमें सभी के लिए स्थान समान रूप से रहा। पंथ निरपेक्षता भारत की विशेषता बनी, लेकिन दूसरी ओर भारत से ही अलग हुए पाकिस्तान ने अपने लिए इस्लामिक गणराज्य बनने का रास्ता चुना, जिसमें जो अल्पसंख्यक रहे, वे आज भी रो रहे हैं । जो शरणार्थी भारत आए, वे क्या अभी अचानक से यहां आ गए हैं ? माना कि भारत सरकार यह सीएए उनके लिए लेकर आ गई? लेकिन क्या इससे पहले नियमानुसार अनुमति लेकर समय-समय पर मुसलमान एवं अन्य जो भी लोग एक बड़ी संख्या में दूसरे देशों से भारत आए और उन्होंने नागरिकता लेनी चाही तो क्या भारत सरकार ने उन्हें वह नागरिकता अभी तक प्रदान नहीं की है ? जो नियमों में चलता है, उसके लिए भारत में हमेशा खुले रहते हैं नागरिकता के द्वार।

सोचिए, क्या इस इतिहास को यूएन नहीं जानता है। समझने के लिए यहां दो विषय हैं, एक-भारत विभाजन के समय से लगातार चलनेवाली पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में अल्पसंख्यकों की दयनीय स्थिति, उनके बीच व्याप्त भय, कन्वर्जन और मौतें ।

दूसरा-पिछले 78 साल में भारत में आए मुसलमान और उनको दी गई भारतीय नागरिकता। आप देखेंगे कि जिन्होंने भी भारत की नागरिकता के लिए नियमों का पालन किया, उन्हें सदैव भारत सरकार नागरिकता देती आई है। जिसमें कि पाकिस्तान समेत बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भी कई मुसलमान भारत आए हैं । ऐसे में यूएन को यह समझना चाहिए कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) किसी भी देश के द्वारा दी जानेवाली नियमित नागरिकता से पूरी तरह भिन्न है! यूएन देखे; पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में कौन अल्पसंख्यक सुखीः सांस्कृतिक, राजनीतिक और भौगोलिक रूप से भी कभी जो भारत (पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश) एक रहा। उस भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप अन्य इस्लामिक गणराज्यों में पिछले सात दशकों में उनके साथ जो अमानवीय व्यवहार किया गया और अब भी किया जा रहा है, यह उनमें से भारत में शरण लेने आए, पूर्व से रह रहे उन लाखों शरणार्थियों के लिए है, जिनके साथ उनके हिन्दू, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी, सिख होने के कारण से अत्याचार किए जा रहे थे। वस्तुत- इस मुद्दे पर यूएन को भारत का विरोध करने के पूर्व यह जरूर बताना चाहिए था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बाद में बने बांग्लादेश में इस्लामिक सत्ता में कौन अल्पसंख्यक सुखी हैं? क्या आज यूएन को इन तीनों देशों में हो रहे अत्याचार दिखाई नहीं देते?

कश्मीर मुद्दे पर चुप रहता है यूएन, भारत को बदनाम करने वाली झूठी रिपोर्ट्स पर भी चुप्पी

वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में 193 राष्ट्र सम्मिलित हैं। इसकी संरचना में महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, सचिवालय, अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद सम्मिलित है। एक तरह से आप इसे वैश्विक न्याय संस्था भी कह सकते हैं। किंतु आप देखिए, यह दुनिया की न्याय बॉडी कैसे भारत को टॉर्गेट कर रही है? भारत में घटी छोटी-छोटी घटनाओं को यहां अनेकों बार बहुत बड़ा करके प्रस्तुत किया जाता रहा है। कश्मीर मुद्दे पर यह पाकिस्तान के सामने चुप नजर आती है। जबकि विश्व जानता है कि उसने भारत की 78 हजार वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा जमा रखा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जैसी तमाम रिपोर्ट्स में जानबूझकर भारत को कमजोर, गलत और अत्याचार करनेवाला बताया जाता है, जबकि यह भारत की सच्चाई नहीं है, इस पर यूएन कभी इस प्रकार की झूठी रिपोर्ट तैयार करनेवाली अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और उन देशों को लताड़ नहीं लगाता, जहां भारत को कमजोर तरीके से प्रस्तुत करने का षड्यंत्र होता है। भारत को विश्व भर में बदनाम करने के प्रयास होते हैं।

यूएन मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहे देशों पर कब गंभीर होगा?

दुनिया के कई ईसाई और इस्लामिक देश खुल कर मानवाधिकारों का हनन कर रहे हैं, वह भी यूएन को आज दिखाई नहीं देता, उन पर यूएन की कोई एक टिप्पणी नहीं आती है । चीन की वुहान लैब में क्या हुआ, यह आज पूरा विश्व जानता है। पूरे विश्व ने एक भयंकर त्रासदी (कोविड-19) वायरस संक्रमण की कम से कम पांच वर्ष लगातार झेली। अनेकों ने अपने परिवार जनों को बिना किसी कारण के गंवाया है और आज भी दुनिया के तमाम देशों में कोरोना का प्रभाव बना हुआ है और मौतें अब भी हो रही हैं । किंतु यह जानते हुए भी यूएन आज तक यह हिम्मत नहीं दिखा पाया कि खुलकर एक बार कह दे कि इस सब के लिए चीन पूरी तरह से दोषी है। दुनिया के कई देशों में जो अब तक लाखों जानें गईं वह चीन के कारण से गई हैं! यह भी देखिए कि कैसे चीन में उइगर मुसलमानों की धीरे-धीरे पहचान तक समाप्त की जा रही है। चीन खुलकर दुनिया के सामने मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है।

वह अपने लिए जा रहे निर्णयों पर इतना सख्त है कि यहां शिनजियांग क्षेत्र में रह रहे डेढ़ प्रतिशत मुसलमानों को एक राजकीय अभियान चलाकर समाप्त कर देने में लगा हुआ है। आतंकवाद के झूठे आरोप लगाकर इन उइगर मुसलमानों को चाइना भयंकर सजाएं देता है और बार-बार कहता है कि शिनजियांग क्षेत्र का सामान्यीकरण हो जाना चाहिए, जिसमें किसी को कोई विशेष पहचान न रहे। कई अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स हैं जो यह बताने के लिए पर्याप्त हैं कि पिछले कुछ सालों में ही चीन में लगभग 20 हजार मस्जिदें ढहा दी गईं। यहां मुस्लिमों को उनकी इस्लामिक मान्यतानुसार दाढ़ी बढ़ाने, जालीदार टोपी, हिजाब, बुर्का पहनने की अनुमति नहीं है।

इतना ही नहीं, मुसलमान खुले में कुरान तक का पाठ नहीं कर सकते, इस पर पूर्ण प्रतिबंध है। संयुक्त राष्ट्र स्वयं भी अपनी जांच में इस बात के साक्ष्य जुटाने में सफल हुआ है कि शिनजियांग क्षेत्र में बलपूर्वक श्रम, यौन अत्याचार, लिंग के आधार पर हिंसा, प्रजनन अधिकारों के उल्लंघन, बड़ी संख्या में इस्लामिक पूजास्थलों का विनाश किया जाता रहा है और यह सब कुछ अभी भी हो रहा है।

लेकिन इतना कुछ जानते हुए भी संयुक्त राष्ट्र को आप देखिए, वह चीन के मामले में चुप दिखाई देता है। कैसा आश्चर्य है ! जो चीन जो मानवाधिकारों को भरपूर उल्लंघन करता है, वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) का स्थायी सदस्य है लेकिन भारत एक श्रेष्ठ और सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ ही चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, परमाणु शक्ति संपन्न, प्रौद्योगिकी हब तथा वैश्विक संपर्क की परंपरा वाला शक्ति सम्पन्न राष्ट्र होने के बाद भी आज पिछले कई वर्षों से सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य का प्राप्त करने के लिए संघर्षरत है।

जैव विविधता हो, पर्यावरण संरक्षण का विषय हो, मानवीय त्रासदी हो या फिर दुनिया के किसी भी कौने में आई कोई महामारी में मदद के लिए खड़े होने का सवाल हो, हर वक्त मानवता की सेवा करने और प्रकृति को बचाने भारत सदैव से नेतृत्व की भूमिका में दिखता है, लेकिन यूएन है कि फिर भी भारत की मोदी सरकार को घेर रहा है, वह भी एक अच्छे निर्णय सीएए के लिए। वास्तव में इस मामले में तब बहुत अच्छा लगता जब यूएन इस उत्तम निर्णय के लिए भारत सरकर की प्रशंसा करता। इससे अच्छा तब ओर लगता जब यूएन की मुख्य कार्यकारिणी यूएनएससी में भारत को सदस्यता देने की वैश्विक जरूरत और विस्तार की अनिवार्यता को देखते हुए स्थायी सदस्यता दिलवाने का प्रयास करती नजर आती।

केजरीवाल के आरोपों से तिलमिलाई बीजेपी, सीएए पर आरोपों की झड़ी लगाई दिल्ली के सीएम ने

नई दिल्ली। केजरीवाल की जबानी कैंची ने चुनाव में सीएए से भाजपा को होने वाले लाभ को कुतरने का प्रयास किया है। केजरीवाल के आरोप कितने गंभीर हैं यह इसी बात से पता चलता है कि उनके बचाव में गृहमंत्री अमित शाह और रविशंकर प्रसाद को आना पड़ा है। हो सकता है आने वाले समय में भाजपा के और बड़े नेता भी मैदान में आये।

केजरीवाल आरोप लगाते रहे है कि बीजेपी झूठ बोलती है। अब वे झूठ के मुकाबिल महाझूठ लेकर आये है। जानकार लोग मानते हैं कि बीजेपी जिस तरह से प्रचार में आगे होती है उसका जवाब विपक्ष में केवल केजरीवाल के पास है। केजरीवाल की बात की काट करने में बीजेपी के नेताओं के पसीने छूट रहे हैं।

क्या आरोप लगाया केजरीवाल ने?

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीएस को लेकर आरोप लगाया है कि भाजपा विदेश-पाकिस्तान और बांग्लादेश में बसे हिन्दू जिनकी संख्या डेढ़ करोड़ से ज्यादा है को भारतीय नागरिकता देने जा रही है और इनको ऐसे स्थान पर बसाएगी जहां बीजेपी के वोटर कम संख्या में है। यहीं नहीं इनके लिए मकान और रोजगार की व्यवस्था करेगी और इस तरह से उनका आरोप है कि विदेशियों को बसाकर उनको रोजगार यहां के लोगों की कीमत पर देगी। केजरीवाल के आरोप इतने तीखे हैं कि भाजपा तिलमिला कर रह गई। केजरीवाल के आरोप गंभीर है। दिल्ली की सात सीटों पर रह रहे 25to40 प्रति। मुसलमान और गरीब झुग्गी में रहने वाले बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग निश्चित रूप से चुनाव में केजरीवाल से प्रभावित हो सकते हैं। यही हाल बंगाल में हो सकता है।

सीएस की वास्तविक स्थिति क्या है?

सीएस लागू होने के बाद दिसंबर 31 दिसम्बर 2014 के पूर्व भारत में आए हुए शरणार्थी जिनकी संख्या लगभग 30 हजार है को भारतीय नागरिकता देने का कानून बनाया गया है। इसके बाद में आने वाले लोगों के लिए यह कानून लागू नहीं होगा। यहां पर केजरीवाल का कहना है कि आने वाले समय में बड़ी तेजी से पलायन बढ़ेगा और शरणार्थियों की संख्या बढ़ती जाएगी और भाजपा अपना वोट बैंक तैयार करने के लिए Cutoff date को आगे बढ़ाकर 2024 भी कर सकती है।

इस मामले में सरकार को सफाई देने के लिए मजबूर करने वाले केजरीवाल महाझूठ का प्रचार सोशल मीडिया पर तेजी से चला रहे हैं और दिल्ली व पंजाब के मतदाताओं को प्रभावित करने की पुरजोर और कोशिश कर रहे हैं।

सीएए के खिलाफ ममता बनर्जी अलग अपना स्टैंड लिए हुए हैं दोनों मिलकर बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ाने की फिराक में है। यह देखने वाली बात होगी कि केजरीवाल के महा झूठ का असर दिल्ली में और दिल्ली के साथ साथ देश के अन्य स्थानों पर क्या होगा।

क्या है सीएए?

The citizenship Amendment act 2019 भारत की संसद ने दिसम्बर 2019 को पारित किया। इससे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगला देश से 31 दिसम्बर 2014 के पूर्व आने वाले वहां के अल्पसंख्यक शरणार्थी को भारत की नागरिकता दी जाएगी।

रेलवे स्टेशन और महाकालेश्वर मंदिर के बीच रोप-वे के विकास, संचालन और रख-रखाव के लिए 188.95 करोड़ रुपये स्वीकृत

उज्जैन। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 15 मार्च को स्टीस्ट् कर कहा है कि मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में उज्जैन जंक्शन रेलवे स्टेशन और महाकालेश्वर मंदिर के बीच वर्तमान रोप-वे के विकास, संचालन और रख-रखाव के लिए हाइब्रिड वार्षिकी माध्यम के अंतर्गत 188.95 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। श्री गडकरी ने कहा कि प्रस्तावित रोप-वे विशेष रूप से तीर्थयात्रा में श्रद्धालुओं की अधिकतम उपस्थिति के दौरान उनके आवागमन में सहायता प्रदान करेगा और यात्रा के समय को 7 मिनट तक कम कर देगा। रोप-वे से प्रतिदिन 64,000 तीर्थयात्रियों को सुविधा मिलेगी।

अतिक्रमण हटाया

उज्जैन। निगम आयुक्त श्री आशीष पाठक के निर्देशानुसार आचार संहिता प्रारंभ होते ही नगर निगम अमले द्वारा सम्पत्ति विरूपण सम्बंधी कार्यवाही प्रारंभ की गई है, जो निरंतर जारी हैं। निगम अतिक्रमण गैंग द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों को निरंतर भ्रमण किया जा रहा है एवं विभिन्न शासकीय एवं सार्वजनिक संपत्तियों, स्थलों से विभिन्न प्रकार के फ्लेक्स, होर्डिंग हटाए जाने के साथ ही दीवारों और अन्य स्थलों पर ऐसी वाल पेंटिंग जिनसे आचार संहिता उल्लंघन होने की आशंका होती है उन्हें पेंट करते हुए मिटाया जा रहा है। यह कार्यवाही सम्पूर्ण शहर में की जा रही है।

उज्जैन में आज भी चलाई जाती है तोप, इसके जरिए देते हैं सेहरी-इफ्तारी की सूचना

उज्जैन। पूरे देश में खुदा की इबादत के रमजान महीने को अल्लाह की इबादत कर मनाया जा रहा है। रमजान में हर दिन सेहरी और इफ्तार के लिए रोजेदारों को अलर्ट करने के वैसे तो कई आधुनिक तरिके हैं। लेकिन, सेहरी का वक्त खत्म हो गया या फिर इफ्तार करने का वक्त हो गया है। इसके लिए आज भी उज्जैन के कोट मोहल्ले में बरसों पुरानी तोप छोड़कर सूचना देने की परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। तोप वाली मस्जिद के सदर मोहम्मद मकसूद बबलू भाई बताते हैं कि कोट मोहल्ला की इस मस्जिद का नाम तोप वाली मस्जिद इसीलिए है, क्योंकि रमजान महीने में यहां सेहरी और रोजा इफ्तार की सूचना तोप चलाकर दी जाती है।

करीब सौ साल से अधिक पुरानी तोप में बारूद भरकर अलसुबह सेहरी और शाम को सूरज ढलते ही इफ्तार के समय तोप चलाई जाती है। ईद के एक दिन पहले चांद दिखाई देने कि सूचना के भी सात बार तोप चलाकर दी जाती है। मस्जिद में तोप चलाने के लिए चार लोगों को जिम्मेदारी दी गई है जो पूरे महीने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते है। इनमें मेहताब भाई, युनूस भाई, परवेज भाई और रईस भाई शामिल हैं।

पूरे शहर में सुनाई देती थी तोप की आवाज

मुस्लिम समाज के बुजुर्ग बताते हैं कि जिस तोप को छोड़कर सेहरी और इफ्तारी की सूचना दी जाती है वह करीब सौ साल से अधिक पुरानी है। कभी पूरे शहर में इसकी आवाज सुनाई देती थी, पर अब इसकी आवाज पुराने शहर में ही सुनाई देती है। कारण यह की अब बड़े-बड़े भवन और होटल आदि बन गए हैं और अनगिनत वाहनों की ध्वनि में तोप की आवाज दब जाती है। सदर मोहम्मद मकसूद बबलू के अनुसार पूरे महीने तोप छोड़ने के लिए लगने वाले बारूद और इससे संबंधित अन्य खर्च का वहन मस्जिद कमेटी ही उठाती है, इसके लिए किसी से चंदा नहीं लिया जाता है।

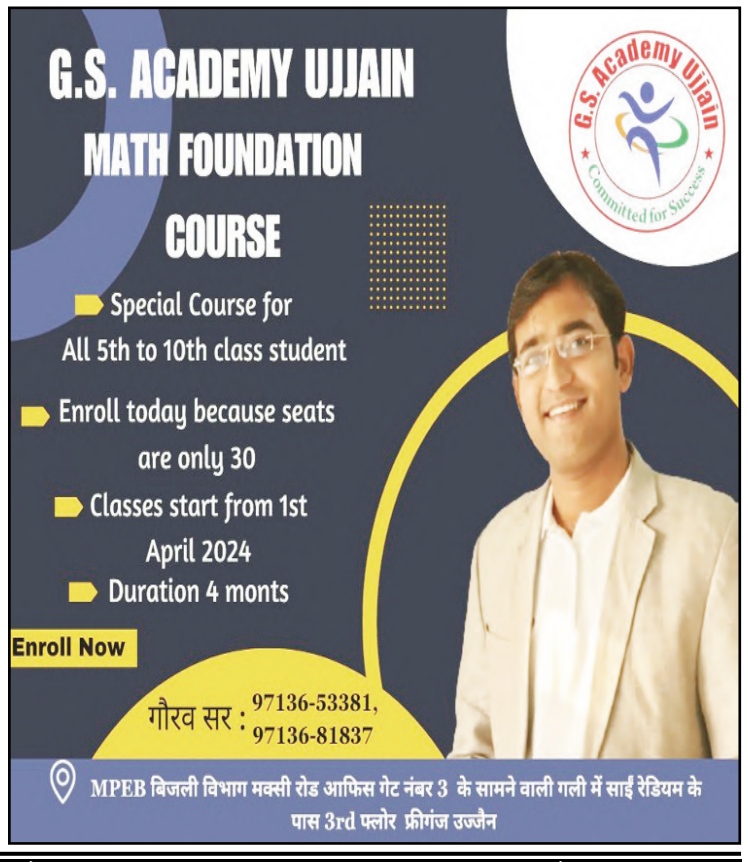

स्वताधिकारी/प्रकाशक मनमोहन शर्मा के लिये साप्ताहिक उज्जैन टाइम्स 110, तिरुपति एवेन्यू, होटल नक्षत्र के पीछे, पंचक्रोशी मार्ग, उज्जैन (म.प्र.) से प्रकाशित एवं ज्योति ट्रेडर्स एवं प्रिन्टर्स न्यू रोड़, उज्जैन से मुद्रित।
● प्रधान सम्पादक : मनमोहन शर्मा मोबा. 9827233734 manmohan680@gmail.com (सभी वाद-विवादों का न्याय क्षेत्र उज्जैन रहेगा)। (म.प्र. शासन से 01-04-1997 से समाचार पत्र विज्ञापनों हेतु अनुमोदित)